Need to abolish contract labour in FCI

श्री सुदामा प्रसाद (आरा) : माननीय सभापति महोदया, भारतीय खाद्य निगम के श्रमिक पे-रोल पर हैं तथा निगम में रेग्युलर श्रमिक हैं। इन नो वर्क - नो पे श्रमिकों का न ही कोई मासिक गारंटी मजदूरी निर्धारित है और न ही इनके लिए सेवा शर्तों का गठन किया गया है। ये श्रमिक वर्तमान में प्रति माह औसतन 5000 रुपए से 10000 रुपए तक मजदूरी ही अर्जित कर पाते हैं, जो जीवन यापन के लिए कम है।

जब श्रमिक ठेका प्रथा में थे, उस समय खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित श्री विवेक मेहरोत्रा कमेटी ने भी इन श्रमिकों को डीपीएस सिस्टम में नियोजित करने हेतु वर्ष 2007 में अनुशंसा की थी, जिसको सरकार ने पत्र दिनांक 01-10-2008 के माध्यम से स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन गोदामों से ठेका प्रथा निषेद्ध किया गया तो वर्ष 2011-12 में इन श्रमिकों को डीपीएस सिस्टम में नियोजित नहीं कर, नो वर्क - नो पे सिस्टम में किया गया। अभी भी कोई मासिक गारंटी मजदूरी नहीं है और न ही श्रमिकों की कोई सेवा शर्त है।

मैं आपके माध्यम से इन श्रमिकों के लिए एफसीआई में नो वर्क नो-पे सिस्टम समाप्त कर डीपीएस सिस्टम में अपग्रेड करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने तथा मेडिकल सुविधा प्रदान करने की मांग करता हूँ।